(ख) रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में 41 करोड़ लोग गरीब हैं। आंकड़े किस वर्ष से संबंधित हैं उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि रिपोर्ट में दी गई अधिकांश सूचना वर्ष 1990 से संबंधित है अतः यह समझा जाता है कि गरीबी के आंकड़े वर्ष 1990 से ही संबंधित हैं। यू. एन डी. पी. के अनुसार सरसरी तौर पर देश की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत तबका गरीब है। इस अनुमान का आधार स्पष्ट नहीं है।

(ग) गरीबी के इसके अपने अनुमानों के आधार पर सरकार ने ग्रामीण एवं कृषि विकास, खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर आधारित एक गरीबी उन्मूलन कार्यनीति तैयार की है। छठी योजना में शुरू किए गए मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी)। सातवीं योजना के दौरान ये कार्यक्रम पर्याप्त उच्च परिव्यय तथा सावधानी से जारी रखे गये। वर्ष 1989-90 में एन आर ई पी तथा आर एल ई जी पी को एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अर्थात जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) में मिला दिया गया था। वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान आई आर डी पी तथा जे आर वाई भी क्रियान्वित किए गये। नेहरू रोजगार योजना वर्ष 1989 से शहरी गांवों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इन कार्यक्रमों को और अधिक तेजी से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जाएगा।

Standing Committee on Agriculture

2639. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Standing Committee on Agriculture appointed under the Chairmanship of Shri Sharad Joshi had been dissolved;

(b) whether the Committee had submitted its final report; and

(c) if so, what are the salient features of the said report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir. With effect from 16th May, 1991, 1991, the Standing Committee on Agriculture ceased to function.

(b) and (c) The Committee did not submit any final report. However, a draft report was submitted by the Committee in the form of National Agricultural Policy—views of Standing Committee on Agriculture.

Backlog of Unemployment

@2640. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the figure of unemployment up to March, 1992 and how much it is expected to rise at the end of Eighth Five Year Plan and by the Year 2000 A.D.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): Backlog of unemployment in March, 1992 is estimated to be around 17 million by weekly status (by weekly status concept, an unemployed is one who, though available for work, did not get work even for one hour during the reference week). Following the strategy envisaged in the Eighth Plan, it is

@Previously Unstarred Question 1595, transferred from 23rd July, 1992.

estimated that unemployment will be reduced to around 10 million by the end of the plan and to about 3 million by 2000 A.D .

जिलास्तरीय विकास योजना तयार किया जाना

@@2641. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिलास्तरीय विकास योजना तैयार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) आठवीं योजना में जिला योजना के महत्व पर जोर दिया जाता रहेगा। योजना आयोग 1969 से जिला योजनाएं तैयार करने के लिए कहता रहा है। राज्यों को जिला योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर योजना मशीनरी को सुदृढ बनाने की योजना के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें मॉडल योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। योजना आयोग के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा तैयार किए गए पांच जिलों के लिए मॉडल योजनाएं तथा जिला योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी हैं। जिला योजनाएं बनाने के लिए ये दिशा निर्देश राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तर स्तरीय योजनाएं बनाने के लिए जिला योजना मशीनरी को अधिक स्वतंत्रता दे। महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित योजनाएं आरम्भ करने के लिए "मुक्त" निधियों के प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य

@@@2642. **श्री विनोद शर्मा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन की विकास-दर के लिए रखा गया लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्य की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन की विकास-दर का क्या लक्ष्य रखा गया था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य कितना होगा; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के के लिए उत्पादन की विकास-दर का लक्ष्य कम रखे जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्रीय विकास दरों का पूर्व अनुमान पिछले कार्य निष्पादन विकास के लिए संभावनाएं तथा योजना की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रकार आठवीं योजना में 5.6 प्रतिशत की लक्ष्य की गई सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रकों की अपेक्षित वृद्धि निम्न प्रकार है :

@@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1737, 24 जुलाई 1992 से स्थानान्तरित।

@@@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1553, 23 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित।